www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
बुधवार 27 फरवरी 2019

दैनिक जागरण

संयम की सीमा समाप्ति के बाद शौर्य प्रदर्शन अपरिहार्य हो जाता है

एक और सख्त संदेश

पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की बहानेबाजी को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि उसे न केवल सबक सिखाया जाए, बल्कि यह संदेश भी दिया जाए कि भारत अब उसकी चालबाजी में आने वाला नहीं है। यह वक्त बताएगा कि पाकिस्तान कोई सही सबक सीखता है या नहीं, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने उसकी सीमा में घुसकर जैश ए मुहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे पर हमला करके यह बता दिया कि भारत के सहने की एक सीमा है। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के साथ पाकिस्तान की मूल सीमा रेखा भी पार कर एक तरह से उसके मर्म पर प्रहार किया। बालाकोट पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय रावलपिंडी से ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान को यह समझ आ जाना चाहिए कि अगर भारत के लड़ाकू विमान बिना किसी बाधा बालाकोट तक पहुंच सकते हैं तो वे रावलपिंडी भी पहुंच सकते हैं। उसे यह भी समझ आना चाहिए कि परमाणु बम का इस्तेमाल करने की उसकी धमकियां अब काम आने वाली नहीं हैं।

बालाकोट में जैश के जिस आतंकी अड्डे को मटियामेट किया गया वैसे तमाम अड्डे पाकिस्तानी सेना के संरक्षण और समर्थन से ही चलते हैं। अभी तक पाकिस्तान ऐसे अड्डों को खत्म करने का दिखावा करने के साथ यह बहाना भी बनाता रहा है कि हम तो खुद ही आतंक के शिकार हैं। यह झूठ न जाने कितनी बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान बेशर्मी से बाज नहीं आ रहा है। बालाकोट में सफल हवाई हमले को अंजाम देने के बाद भारत दुनिया को यह संदेश देने में भी कामयाब रहा कि उसने पाकिस्तान को निशाना बनाने के बजाय उसके यहां कायम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। वायुसेना ने अपनी पराक्रम क्षमता और साहस का जो परिचय दिया वह पाकिस्तान के साथ विश्व समुदाय को भी एक संदेश है। वह यह संदेश इसीलिए दे सकी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जरूरी राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया। चूंकि पाकिस्तान के लिए दुनिया को यह समझाना मुश्किल होगा कि उसके यहां आतंकी अड्डे नहीं चल रहे थे इसलिए उसके लिए कोई कार्रवाई कर पाना भी कठिन होगा। उसे यह भय भी सताएगा कि उसकी ओर से भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो उसे कहीं अधिक करारा जवाब मिलेगा। पता नहीं कि फिलहाल लीपापोती के साथ तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान आगे क्या करेगा, लेकिन भारत के लिए यह जरूरी है कि वह उस पर दबाव बनाए रहे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह काम नहीं किया गया था। अब यह जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आसानी से सुधरने वाला नहीं है। इसी के साथ भारत सरकार को कश्मीर के हालात सुधारने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान वहां के हालात का ही फायदा उठा रहा है। कश्मीर को शांत करने के प्रयासों को राजनीतिक एकजुटता का सहारा मिलना चाहिए। यह अच्छा नहीं हुआ कि पुलवामा हमले के बाद बनी राजनीतिक एकजुटता छिन्न-भिन्न हो रही थी। अब ऐसा न हो, यह देखना सबकी जिम्मेदारी है। राजनीतिक नेतृत्व के साथ आम जनता का भी एकजुट रहना और दिखना समय की मांग है।

सियासी हत्याएं

पश्चिम बंगाल में सियासी हत्याएं नई नहीं हैं। राजनीतिक हिंसा के लिए बंगाल दशकों से कुख्यात रहा है, परंतु इस समय न तो कोई चुनाव हो रहा है और न ही चुनाव खत्म हुआ है। फिर भी बीते 20 दिनों में सिर्फ तृणमूल के विधायक समेत तीन नेताओं व एक कार्यकर्ता की हत्या हो चुकी है। वहीं विधायक की गाड़ी पर गोलीबारी से लेकर तृणमूल पार्षद को गोली मारने की वारदात हो चुकी है। इन घटनाओं के लिए हत्या के कुछ देर बाद ही तृणमूल ने भाजपा पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। नदिया के कृष्णगंज के विधायक की हत्या में तो तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कद्दावर नेता मुकुल रॉय को भी नामजद आरोपी बनाया गया है। इस घटना के महज कुछ दिनों बाद ही दक्षिण 24 परगना जिले के बजबज में तृणमूल पार्षद को गोली मार दी गई। इससे पहले इसी जिले में तृणमूल विधायक की गाड़ी पर गोलाबारी की गई थी। इसके बाद अब दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग और कुलतली के अलावा मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में रविवार की रात व सोमवार तड़के दो तृणमूल नेता और एक कार्यकर्ता की गोली मार कर हत्या कर दी गई। इन हत्याओं को लेकर कैनिंग पश्चिम के तृणमूल विधायक श्यामल मंडल ने बिना जांच पूरी हुए ही भाजपा को दोषी करार दे दिया। हालांकि भाजपा ने तृणमूल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए आपसी गुटबाजी का नतीजा बताया। यहां सवाल यह उठता है कि हत्या के कुछ समय बाद ही क्यों सियासी बयानबाजी शुरू हो जा रही है? क्या ऐसे में जो असली दोषी है वह बच नहीं निकलेगा? इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि, जांच से पहले ही दोषी कौन है यह बयान आ जाने के बाद पुलिस की जांच भी प्रभावित हो जाती है। वहीं सवाल यह भी उठता है कि जब सत्तारूढ़ दल के नेता व कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम लोगों का क्या हाल होगा? इसीलिए पुलिस प्रशासन को चाहिए कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आवश्यक ठोस कदम उठाए। साथ ही विशेष इनपुट जुटाएं ताकि अपराध होने से ही रोके जा सकें।

पाकिस्तान के मनोबल पर प्रहार

ब्रिगेडियर आरपी सिंह

बालाकोट में हुए हवाई हमले के बाद पाकिस्तान में अफरातफरी का माहौल है तो यह इसका ही परिचायक है कि उसके विकल्प सीमित हो गए हैं

पुलवामा हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायु सेना के मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने देश के अलग-अलग हिस्सों से उड़ान भरी। उन्होंने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा स्थित बालाकोट में आतंकी संगठन जैश के ठिकानों पर हमले किए। बालाकोट उन्नीसवीं सदी से ही जिहाद के लिए कुख्यात रहा है। सैयद अहमद बरेलवी ने बालाकोट की धरती से महाराजा रंजीत सिंह के खिलाफ जिहाद की शुरुआत की थी। रंजीत सिंह की सेना ने एक साहसिक अभियान में बरेलवी के संगठन को खत्म करते हुए 1831 में वहां पनप रहे जिहाद के उन्माद पर विराम लगा दिया था। कुछ इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को संदेश दिया कि बस अब बहुत हुआ। बालाकोट में भारतीय वायुसेना का सफल हवाई हमला एक शानदार सफलता है। यह हवाई हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। वह हतप्रभ रह गया। भारतीय वायुसेना ने इस साहसिक सैन्य अभियान के लिए जिस तरह लड़ाकू विमानों, शस्त्रों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का चयन किया गया वह उसके पेशेवर अंदाज की उत्कृष्ट मिसाल है। हमारी वायुसेना ने एकदम सटीक-संतुलित आकलन किया और नियंत्रित हमले से अपना उद्देश्य पूरा किया। इस पर हैरानी नहीं कि पाकिस्तान की शुरुआती प्रतिक्रिया मुकरने वाली ही रही। ऐसा ही रवैया उसने सर्जिकल स्ट्राइक के समय भी अपनाया था। भारत के हवाई हमले ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया है। पुलवामा हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक मोर्चे पर अलग-थलग करने, आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटा था। अब उसने उसे सैन्य रूप से भी तगड़ा झटका दिया है। यह उसे झकझोर कर उसका मनोबल तोड़ने वाला साबित होगा। वैश्विक बिरादरी से पाकिस्तान को काटने के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत कूटनीतिक मोर्चे पर बहुत अच्छी स्थिति में है। आतंकी गतिविधियों के लिए अधिकांश देश पहले ही पाकिस्तान की कड़ी भर्त्सना कर चुके हैं। यहां तक कि भारत चीन पर भी दबाव बना रहा है कि वह पाकिस्तान पर अपना नजरिया बदले। भारत को पाकिस्तान पर सैन्य शिकंजा कसने के लिए ईरान और अफगानिस्तान को साथ लेकर पाकिस्तान से लगी सीमा पर एक मोर्चा बनाना चाहिए। हालांकि सऊदी अरब और अमेरिका के रुख को देखते हुए ऐसे सैन्य समन्वय को लेकर तेहरान जरूर कुछ हिचक दिखा सकता है। नई दिल्ली को तेहरान को आश्वस्त करना होगा कि लड़ाई में उलझने के बजाय मामला केवल सैन्य दबाव बढ़ाने तक सीमित रहेगा। इससे पाकिस्तान को अपनी उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर सेना की तैनाती के समीकरणों को नए सिरे से साधना होगा। इससे भारत का काम आसान हो जाएगा और पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की हिमाकत नहीं करेगा।

पाकिस्तान इतनी आसानी से मानने वाला नहीं। उसकी आर्थिक रीढ़ भी तोड़नी होगी। मुश्किलों से जूझ रहे पाकिस्तान को इस समय अंतरराष्ट्रीय मदद की सख्त दरकार है। यह भारत की कूटनीतिक कोशिशों का ही नतीजा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पेरिस में हुई हालिया बैठक में पाकिस्तान को ग्रे सूची में कायम रखा गया। भारत की निरंतर कोशिशें पाकिस्तान को उत्तर कोरिया जैसा बना सकती हैं। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं इस्लामाबाद को काली सूची में डालकर उससे मुंह फेर सकती हैं।

अवधेश राजपूत

भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षक बाजार है। नई दिल्ली को इन कंपनियों के आगे शर्त रखनी चाहिए कि अगर वे भारत में कारोबार करना चाहती हैं तो उन्हें पाकिस्तान से किसी तरह का कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रखना होगा। अपने निजी एवं कूटनीतिक संबंधों का लाभ उठाते हुए मोदी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों से पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद को भी रोकने की कोशिश करें। इसी तरह अगर चीन पाकिस्तान पर अपना रवैया नहीं बदलता तो भारतीय राजनीतिक दल जनता को चीनी कंपनियों के उत्पादों के बहिष्कार के लिए लामबंद करें। एक ऐसे समय जब अमेरिका चीनी आयात पर सख्ती कर रहा है तो बीजिंग भारत जैसे बाजार को गंवाना नहीं चाहेगा।

भारत के पास सैन्य विकल्पों की भी कमी नहीं है। जमीनी हमलों और नियंत्रण रेखा पर अहम चौकियां कब्जाने से लेकर वैसे अचूक हवाई हमले भी किए जा सकते हैं जैसा गत दिवस किया गया। गुलाम कश्मीर में आतंकी ठिकानों को बार-बार निशाना बनाया जाना चाहिए। आतंकी ठिकानों और प्रशिक्षण शिविरों के लिए मिसाइल और ड्रोन हमलों के बारे में भी सोचा जा सकता है। इसके अलावा मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को इजरायली शैली वाले खुफिया अभियानों से ठिकाने लगाया जा सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक भी एक विकल्प है, लेकिन कार्रवाई करके निकलने के बजाय सुरक्षा बल उस हिस्से पर काबिज भी हो सकते हैं। बलूची, सिंधी, पश्तूनों, गिलगित-बाल्टिस्तान और गुलाम कश्मीर में कश्मीरियों की मदद के लिए भी भारत को खुफिया अभियान चलाने चाहिए। इन अशांत इलाकों में अलगाववाद की आग भड़की हुई है, जिसे भुनाना चाहिए। बलूची स्वतंत्रता सेनानियों की मदद के लिए पाकिस्तान की तकरीबन एक हजार किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भी काफी काम आ सकती है। पाकिस्तान को 'आतंकी देश' घोषित करने की दिशा में भी कदम उठाए जाने चाहिए। इसी तरह सिंधु जल समझौता भी खत्म करने पर विचार करना चाहिए। पाकिस्तान की ओर बहने वाली नदियों पर बांध बनाकर पानी को सामरिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। सरकार को कश्मीर में अलगाववादी नेताओं पर भी शिकंजा कसना होगा। उनकी सुरक्षा हटाने के साथ ही ऐसे उपाय भी किए जाएं ताकि उन्हें आर्थिक खामियाजा भी भुगतना पड़े। उन्होंने अनुचित तरीकों से भारी धन-संपदा बनाई है। कश्मीरी पंडितों की जमीन कब्जाकर उन्होंने मॉल और प्लाजा बना लिए हैं। उन्हें जब्त किया जाना चाहिए। सरकार को जम्मू-कश्मीर के संदर्भ में धारा 370 की भी समीक्षा करनी चाहिए। सभ्य व्यवहार का जिम्मा केवल सरकार का नहीं है, बल्कि यह परस्पर होना चाहिए।

पाकिस्तान भारत की राह में एक बड़ा कांटा है और उसका यह चरित्र कभी नहीं बदलने वाला। पाकिस्तान के आतंकी उन्माद से निपटने के लिए दीर्घकालिक नीतियों की दरकार होगी। पाकिस्तान या उसके पिट्ठू अगर भारत पर कभी बुरी नजर डालें तो उन्हें तत्काल रूप से जवाब देने के लिए भारत को आकस्मिक योजना तैयार करनी चाहिए। सुरक्षा बलों के लिए एक सामान्य संचालन संहिता तैयार की जानी चाहिए कि विशेष हालात में वे स्वतः कोई निर्णय कर सकें। बालाकोट में हुए हवाई हमले के बाद पाकिस्तान के सभी वर्गों में अफरातफरी का माहौल है तो इसी का परिचायक है कि उसके विकल्प सीमित हो गए हैं। अपेक्षित परिणामों के लिए भारत को व्यावहारिक नीति बनानी होगी। इस साहसिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तारीफ भारतीय वायुसेना की भी करनी होगी जिसने अपने अद्भुत शौर्य की मिसाल कायम की है।

(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं)

response@jagran.com

जरूरी था यह करारा जवाब

दिव्य कुमार सोती

सर्जिकल स्ट्राइक ने पाक के खिलाफ जिस सामरिक खिड़की को खोला था वायुसेना की कार्रवाई ने उसे और बड़ा कर दिया है

आखिर वह काम हुआ जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तान में जैश ए मुहम्मद के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इसमें जैश के लगभग तीन सौ आतंकी मारे गए। यह बीते कई दशकों में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रायोजित छद्म युद्ध के विरुद्ध अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। वायुसेना की इस कार्रवाई के व्यापक सैन्य और सामरिक परिणाम होंगे। भारतीय वायुसेना के मिराज-2000 लड़ाकू विमानों ने यह हमला पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में किया। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ नियंत्रण रेखा पार की, बल्कि पाकिस्तानी सेना की भारी उपस्थिति वाले पाक कब्जे वाले कश्मीर को भी सफलतापूर्वक पार किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन हमारे लड़ाकू विमान न केवल जैश के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने, बल्कि सकुशल भारतीय सीमा में लौटने में भी कामयाब रहे। ऐसा पिछले कई दिनों से पाक वायु सेना के एलर्ट पर रहने और लगातार गश्ती उड़ान भरने के बावजूद हुआ। यह पाकिस्तानी वायु सेना की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अभी तक यह माना जाता था कि पाकिस्तानी वायुसेना करीब तीन हफ्ते तक तो भारतीय वायुसेना के लिए चुनौती पेश कर सकती है। अब इसे लेकर संदेह पैदा हो गया है। भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान की जमीनी वायु रक्षा प्रणालियां भी नाकाम साबित हुईं।

ऐसी कोई खबर नहीं है कि पाकिस्तानी सेना ने भारतीय लड़ाकू विमानों पर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी हो या एंटी एयर क्राफ्ट गन का प्रयोग किया हो। पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली उस समय भी नाकाम साबित हुई थी जब अमेरिकी कंमाडो ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में घुस कर मार डालने में सफल हुए थे। तब भी पाकिस्तान में बहुत हंगामा हुआ था कि कैसे पाकिस्तानी रडार अमेरिकी हेलिकॉप्टरों की घुसपैठ से अनजान रहे। तब पाकिस्तानी फौज ने यह बहाना बनाया था कि अमेरिकी हेलिकॉप्टर अफगानिस्तान की ओर से घुसे थे, जबकि पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारतीय सीमा पर केंद्रित थी। बालाकोट में भारतीय हमला पाक कब्जे वाले कश्मीर से बाहर पाकिस्तान की धरती पर उस खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में किया गया जहां न सिर्फ भारत के विरुद्ध आतंकवाद फैला रहे जैश ए मुहम्मद जैसे संगठन सक्रिय हैं, बल्कि अफगानिस्तान में लड़ रहे तालिबान और हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठनों के भी ठिकाने हैं। अफगानिस्तान में पिछले 18 वर्षों से तालिबान से जूझ रहे अमेरिका ने इस इलाके में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन हमले तो किए, परंतु उसने भारत की तरह आतंकी ठिकानों पर बमबारी नहीं की।

पाकिस्तान को लगता था कि भारत अगर कोई कार्रवाई करेगा भी तो वह नियंत्रण रेखा के आसपास पीओके तक सीमित रहेगी, लेकिन भारत ने कहीं अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भारत का प्रहार न सिर्फ कश्मीर में सक्रिय जैश ए मुहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के लिए आघात है, बल्कि अफगानिस्तान में सक्रिय आइएसआइ के पिट्ठू तालिबान के लिए भी चेतावनी है कि अगर अमेरिकी फौज के अफगानिस्तान से जाने के बाद उन्होंने भारतीय हितों को निशाना बनाया तो उन्हें भी ऐसे ही हमले झेलने पड़ सकते हैं। इस सैन्य कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों में भारत की महत्ता बढ़ेगी। यह ध्यान देने योग्य है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले साफ कहा था कि भारत पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। इस बार अमेरिका ने भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की जैसा कि वह पहले किया करता था। संभवतः अमेरिका भी चाहता है अफगानिस्तान में उसकी सैनिक तैनाती घटने के बाद इस इलाके में पाकिस्तान समर्थित जिहादी आतंकियों का प्रभुत्व फिर से कायम न हो। जाहिर है कि ऐसा होने से रोकने में एकमात्र सक्षम देश भारत ही है। भारतीय वायुसेना ने 1971 के भारत-पाक युद्ध के बाद पहली बार सीमा पार कर पाकिस्तान पर हमला किया है। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 1998 में भारत और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बाद यह पहली बार है कि हमारी वायु सेना ने सीमापार कार्रवाई की। वायुसेना को ऐसी इजाजत न कारगिल युद्ध के दौरान मिली थी और न ही 26/11 मुंबई हमलों के बाद, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी सूरत में परमाणु हमले का हौव्वा खड़ा कर रखा था। साफ है कि मोदी सरकार इस साहसिक कदम के लिए प्रशंसा की हकदार है। इस एक कदम ने पाकिस्तान के परमाणु हमले की धौंस की हवा निकाल दी है। अब अगर पाकिस्तान किसी तरह की जवाबी कार्रवाई करता भी है तो न सिर्फ पूरे विश्व में आतंकियों के बचाव में युद्ध करता दिखेगा, बल्कि भविष्य में आतंकी हमले की सूरत में भारत को फिर से ऐसी कार्रवाई करने से रोक नहीं पाएगा। भविष्य में परमाणु बम को ढाल बनाकर भारत के विरुद्ध आतंकवाद प्रायोजित करना अब पाकिस्तान के लिए मुफ्त का सौदा नहीं रह जाएगा। हालांकि अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तानी फौज छल से कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर सकती है। इसमें नियंत्रण रेखा पर आतंकी हमले के साथ भारतीय सैनिक ठिकानों पर हवाई हमलों का प्रयास भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा यह दिखाने के लिए कि पाकिस्तान भारतीय कार्रवाई से डरा नहीं है, आइएसआइ भारत में और आतंकी हमले भी करा सकती है। ऐसी स्थिति में सैन्य तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि भारत अपनी सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकता है।

भारतीय वायुसेना की इस साहसिक कार्रवाई के साथ आतंकवाद के विरुद्ध हमारी जंग खत्म नहीं होती है, बल्कि वह सही तरह से शुरू होती है और वह अभी लंबी चल सकती है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान के विरुद्ध जिस सामरिक खिड़की को खोला था उसे इस कार्रवाई ने और बड़ा कर दिया है। हमें यह याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के कब्जे में अभी भी हाजीपीर जैसे सामरिक रूप से इलाके हैं जिनके जरिये वह भारत में आतंकी घुसपैठ जारी रख सकता है। इसी तरह वहां जमात उद दावा जैसे संगठन भी हैं जिनके हजारों हथियारबंद सदस्य हैं। कट्टरपंथी मदरसों का वह तंत्र भी अभी पाकिस्तान और कश्मीर में सुरक्षित है जो आतंकियों को तैयार करता है। इस सबके बावजूद इतना तय है कि इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में आतंकी और उनके आका उस बेफिक्री से नहीं रह पाएंगे जैसे पहले रहते थे।

(लेखक कांउसिल फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

उपदेश

जीवन में उपदेशों की अहम भूमिका होती है। उन्हें लेकर तमाम बहस भी जारी हैं। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि उपदेश सुनने वाले पहले जैसे नहीं रहे या सुनाने वालों की वाणी में वह ओज नहीं कि सुनने वालों का मन-मस्तिष्क बदल जाए। ग्रंथों में शब्द ब्रह्म कहा गया है तो वक्ता-श्रोता के बीच शब्द ब्रह्म आखिर क्यों निष्प्रभावी हैं? किसी धार्मिक आयोजन में वक्ता तो एक होता है जबकि श्रोता अनेक होते हैं। अगर अच्छे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ा तो मतलब यही निकलता है कि सभी श्रोता अपात्र थे? फिर धार्मिक आयोजन का क्या औचित्य? उपदेशक तो इसी उद्देश्य से निकला है कि वह समाज बदल देगा। यदि नहीं बदल पाया तो उसे भी सार्वजनिक रूप से यह कहना चाहिए था कि वह अपने अभियान में असफल हो गया, लेकिन कोई भी उपदेशक ऐसा कहने को तैयार नहीं।

दरअसल सदुपदेशों के बावजूद सदाचार का लगातार चीरहरण बढ़ रहा है तो सबसे पहले अंगुली उपदेशक पर ही उठेगी। जमाने को दोष देते समय उपदेशक को अपना भी दोष देखना चाहिए। कोई उपदेशक अपना चरण स्पर्श करने वालों से यह नहीं पूछता कि चरण स्पर्श करने वाला अपने माता-पिता की सेवा करता है या नहीं? यदि नहीं तो वह उपदेश सुनने के योग्य नहीं और वह उपदेश-स्थल से तत्काल उठ कर चला जाए। हो यह रहा है कि उपदेशों के नाम पर किसी व्यापारी की तरह अपने उपदेश-उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कोई उपदेशक यह कहते नहीं देखा जाता कि उसे पैसा देने के बजाय किसी गरीब के इलाज, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा, किसी वस्त्रहीन को तन ढकने के लिए पैसा खर्च किया जाए। कहते भी हैं तो वह सीधे नहीं, बल्कि उपदेशक के माध्यम से ही किया जाए। अब यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। धनसंग्रह शुरू हो जाता है। अनेक ऐसे लोग हैं जो प्रचार तंत्र और अन्य माध्यमों की मदद से वे सारे काम शुरू करने लगते हैं जो व्यक्ति को ही कमजोर नहीं करते, बल्कि उसकी वाणी को भी कमजोर बनाते हैं। फिर ऐसे लोगों की बात का समाज पर असर पड़ेगा, यह संभव ही नहीं। उपदेश देने वालों को चाहिए कि वे पहले अपना आचरण सुधारें फिर किसी को सुधारने के लिए सोचें।

सलिल पांडेय

चिंतित करता नशे का फंदा

नरपत दान चारण

जिस युवा आबादी के कारण हम फायदे की बात करते हैं, वही युवा तबका नशे के दलदल में स्वयं को तबाह कर रहा है

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय की ओर से हाल में 'एम्स' के नेशनल ड्रग्स डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के सहयोग से देश में नशे की लत की व्यापकता पर कराए गए एक सर्वेक्षण की भयावह रिपोर्ट सामने आई है। इसमें देश के 26 राज्यों के 186 जिलों में 4,73,569 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर किए गए नशे के सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट का शीर्षक है 'भारत में मादक पदार्थों के उपयोग का चलन और व्यापकता।' इसके अनुसार 16 करोड़ भारतीय शराब का सेवन करते है। इसमें अधिकांश युवा हैं।

रपट के अनुसार मध्य प्रदेश, छतीसगढ़, पंजाब, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में शराब की सबसे अधिक खपत होती है। वहीं देश में 2.8 फीसद लोग भांग, गांजा और चरस का सेवन करते हैं, दो फीसद लोग अफीम, एक फीसद लोग हेरोइन तथा एक फीसद लोग नींद की गोली खाने की लत के शिकार हैं। रपट में बताया गया है कि नशे के छुटकारे के लिए इलाज की सुविधा कम होने के कारण नशा छोड़ने में सफलता नहीं मिल पा रही है। हालांकि नशा एक वैश्विक समस्या है, लेकिन हमारे देश में युवाओं में इसकी बढ़ती प्रवृत्ति चिंताजनक है। अगर हमारे युवादेश को देखें, जहां लगभग 40 करोड़ से अधिक युवा आबादी है जो कि देश का भविष्य है, वही युवा मुख्य रूप से नशे के जाल में छटपटा रहा है। भारत के संदर्भ में ग्लोबल एडल्ट टोबेको सर्वे 2016-17 की रिपोर्ट बताती है कि देश के 21.4 फीसद युवा धुआं रहित तंबाकू का सेवन करते हैं।

हालांकि इसमें धुआं युक्त तंबाकू का उपयोग करने वालों की गणना शामिल नहीं की गई है। अन्यथा यह आंकड़ा और बढ़ जाता। गौरतलब है कि तंबाकू सेवन से देश में हर साल करीबन 10 लाख लोग अकाल मौत का शिकार हो जाते हैं। आज औसतन 17 साल का युवा किसी न किसी नशीली वस्तु का सेवन करना शुरू कर रहा है। नशे से न केवल युवा शक्ति, बल्कि देश खोखला हो रहा है। अब सवाल यह भी उठता है कि जिस युवा वर्ग के कारण हम युवा देश होने का गर्व कर रहे हैं, वही युवा नशे के दलदल में स्वयं को तबाह कर रहा है और अपराधों में शामिल हो रहा है, मगर हम उसे नशे के चंगुल से बचाने के कोई ठोस उपाय क्यों नही कर पा रहे हैं?

आखिर आज समाज और सरकार नशीले पदार्थों को क्यों रोक नहीं पा रहे हैं? जब इन सवालों का जवाब मिलेगा तभी कोई उपाय हो सकता है। आज देश का भविष्य नशे में क्यों फंसा है? इसके जवाब में तो बहुत ही वजहें गिना दी जाती हैं जैसे अलगाव, अवसाद, बेरोजगारी, मगर इससे बचाने के उपाय कोई नहीं सुझा रहा है। बेशक आज नशा रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पारिवारिक और सामाजिक सामूहिक संकल्प और नशा मुक्ति संस्थाओं के साथ ही सरकार को भी नशे की विरुद्ध अभियान चलाना होगा। नशे के अवैध कारोबार को कठोरता से कुचलना होगा। केवल जागरूकता से काम नहीं चलेगा, इसकी रोकथाम के लिए रोडमैप बनाना पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में युवा नशा मुक्ति आंदोलन को शामिल करना चाहिए। तभी इस मुहिम में सफलता मिल पाएगी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

बाजी पलटने वाली सिद्ध होगी योजना

मनरेगा से बेहतर किसान सम्मान योजना शीर्षक से लिखा आशुतोष झा का लेख योजनाओं की वास्तविकता को बयां कर रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बरसों से इस बात से वाकिफ थी की मात्र फसलों के एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने या किसानों को मुफ्त में खाद, बीज आदि उपलब्ध कराने से उनकी दशा नहीं बदलने वाली है, क्योंकि किसानों की गरीबी की असली वजह अपनी फसल को हरा-भरा रखने के लिए सूदखोरों के चंगुल में फंसी किसान की किस्मत को माना जाता है। इसे सीधे तौर पर हाथ में धनराशि देकर ही बचाया जा सकता है। मनरेगा में किसानों को काम करना पड़ता है, तब जाकर खाते में पैसा आता है, लेकिन इस किसान सम्मान निधि योजना में काम का मुंह ताकने की कोई जरूरत नहीं है। लघु और सीमांत किसान इतने पैसे में खाद पानी का तो प्रबंध कर ही सकता है। यह बात काफी समय से सरकार के कानों तक जा रही थी कि किसानों को जब तक रुपया उनके हाथ में नहीं दिया जाता, तब तक न तो उनका मन बदला जा सकता है और न ही उनकी माली हालत। किसान सम्मान निधि योजना मनरेगा से कई गुना बेहतर है। जो केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि मोदी सरकार के लिए भी गेमचेंजर साबित होगी।

पिंटू सक्सेना, लखनऊ

देश के वीरों को सच्ची श्रद्धांजलि

1960 से प्रतीक्षित 40 एकड़ जमीन पर फैले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन कर देश को समर्पित करना और अगली सुबह मंगलवार को 3.48 मिनट पर वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में 300 से ज्यादा पाक पोषित आतंकियों का सफाया करना और शत-प्रतिशत सफल ऑपरेशन कर वापस लौटना पुलवामा और अन्य जगहों पर शहादत पाए वीर जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि ही है, जिसकी पुष्टि देश के विदेश सचिव विजय गोखले ने की। भारत सरकार द्वारा विश्व के अग्रणी और मित्र देशों को सुबूत के साथ पाक पोषित पुलवामा आतंकी घटना से अवगत कराना देश की सफल कूटनीतिक जीत भी है।

दीपक गौतम, सोनीपत

देश में खुशी की लहर

भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में चल रहे सबसे बड़े आतंकी कैंप को ध्वस्त कर पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को बारह दिन बाद सच्ची श्रद्धाजंलि दी है। आज हर भारतवासी खुश है और अपनी भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है। पाकिस्तान इस कार्रवाई से तिलमिला गया है। पहले आर्मी के हाथ खुले छोड़ने की बात होती रहती थी, लेकिन आज हिंदुस्तान सेना की स्वतंत्र कार्रवाई का गवाह बना है। आतंकी देश समझ लें कि भारत किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं है और करारा जवाब देने के लिए तैयार है। पूरे भारत देश में जगह-जगह लोग खुशी मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि आतंकी हमले का मुहंतोड़ जवाब दिया जाएगा, आज वो सच होता नजर आ रहा है। बालाकोट, चकोटी और मुज्जफराबाद यह पाकिस्तान के आतंकी ट्रेंनिग कैंप थे जो अब भारतीय वायु सेना ने तबाह कर दिए हैं। पूरा देश भारतीय वायुसेना के शौर्यपूर्ण कार्य को नमन करता है और दुश्मन आतंकी देश को बता देना चाहता है कि हिंदुस्तान जवाब देने में सक्षम है। इसके साथ ही पाकिस्तान को यह भी समझ लेना चाहिए कि भारत के धैर्य की भी एक सीमा है और उसके पार होने पर वह चुप नहीं बैठेगा।

ramdevtanwar@gmail.com

बेटियां सबसे आगे

खेल का मैदान हो या पुरस्कार की दौड़ हमेशा भारत के तिरंगे की आन बान शान को बेटियों ने ही बचाया है। ओलंपिक खेल हो, एशियाड खेल कॉमनवेल्थ गेम हो जब भी कोई भारतीय अगर पदक जीतता है तो वह महिलाएं यानी कि भारत की बेटियां ही होती हैं। इसी तरह हापुड़ उत्तर प्रदेश की दो महिलाओं ने ऑस्कर जीतकर यह दिखा दिया कि अगर लोग कठिन मेहनत करें, परिश्रम करें तो किसी भी क्षेत्र में सफलता कामयाबी को जरूर चूमती है। शिक्षा के अभाव में तथा विभिन्न प्रकार की परेशानियों को झेलते हुए जिस तरह इन महिलाओं ने अन्य महिलाओं को भी जागरूक किया है वह काबिल-ए-तारीफ है। ऐसी अन्य महिलाओं की कहानियों को और इनके किए गए परिश्रम को आगे लाना चाहिए ताकि और लोग भी इससे प्रेरित हों।

विजय कुमार धनिया, नई दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।